

एस.सी.के.

ए.एल. बहरी, जे. के समक्ष

वीना सिक्का (श्रीमती),-याचिकाकर्ता।

बनाम

श्रीमती. शकुंतला जाखू, प्रतिवादी।

1990 की सिविल मूल अवमानना याचिका संख्या 391।

28 सितंबर 1990.

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971—धारा . 20— अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत के लिए सीमा—रिट याचिका में जारी निर्देश—विशेष अवकाश याचिका ऐसे आदेश के खिलाफ दायर की गई - निर्देशों का अनुपालन न करना - जैसे गैर-अनुपालन जानबूझकर नहीं - अवमानना का कोई मामला नहीं पाया गया।

निर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है जैसा कि उत्तर में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट रोस्टर तय करने का अपना समय लेता है। जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवादी से इसे लागू करने की उम्मीद नहीं थी उपरोक्त रिट याचिका में पारित अंतिम आदेश जो है पियारा सिंह के मामले में निर्णय के आधार पर जो उच्चतम न्यायालय में अपील का विषय रह चुका है। अवमानना कार्यवाही में यह संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की अनुमति देने पर तुरंत उत्तरदाताओं को अपील के अधिकार का सहारा लिए बिना उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने का तत्व गायब होगा। अतः ऊपर बताई गई परिस्थितियों में इस अवमानना याचिका पर आगे बढ़ना उचित नहीं माना गया है

(पैरा 5)

माना गया कि अधिनियम की धारा 20 के अवलोकन से पता चलता है कि जिस तारीख को अवमानना का आरोप लगाया गया है, उस तारीख से एक वर्ष के बाद, न्यायालय को अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करनी है। यदि याचिकाकर्ता की यह दलील स्वीकार कर ली जाती है कि अवमानना उसी दिन की गई थी जिस दिन रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, तो अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 20 में से धारा 20 का प्रावधान उसके रास्ते में आ जाएगा। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता एक के बाद एक अभ्यावेदन दाखिल कर रहा था, किसी भी तरह से परिसीमा की अवधि को नहीं बढ़ाएगा।

(पैरा 6)

वीना सिक्का (श्रीमती) बनाम. श्रीमती शखुंटला जाखू (ए.एल. बहरी, जे.

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी प्रतिवादी के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की जाए और उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाए।

एम. एस. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सरिता गुप्ता, अधिवक्ता के साथ याचिकाकर्ता के लिए

एल. पी. सूद, डी.ए. हरियाणा प्रतिवादी के लिए

निर्णय

ए एल बहरी, जे.

(1) अवमानना न्यायालय अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर इस याचिका में न श्रीमती. वीना सिक्का ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश सी.डब्ल्यू.पी. 1988 का क्रमांक 6150 दिनांक 25 जुलाई 1988 के उल्लंघन का आरोप लगाया आदेश निम्नानुसार पारित किया गया:-

“रिट याचिका के पैराग्राफ 8 में इसका उल्लेख किया गया है आदेश अनुलग्नक पी.2 दिनांक 4 जुलाई 1988 के बावजूद याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं

8 अगस्त 1988 के लिए प्रस्ताव की सूचना।

केवल दस्ती. यथास्थिति यथास्थिति आज भी विद्यमान है।”

परिशिष्ट पी. 2 जैसा कि उपरोक्त आदेश में उल्लेखित है, दिनांक 4 जुलाई 1988, एस.एस.एस. द्वारा याचिकाकर्ता को जनरल फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उसके चयन के बारे में भेजी गई सूचना। यह बता दें कि पहले वह उक्त पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत थीं। 27 जुलाई 1988 को यानि उपरोक्त आदेश के दो दिन बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त (कार्यमुक्त) कर दी गई 22 जुलाई, 1988 से प्रभावी)। समाप्ति का कथित आदेश दिनांक 21 जुलाई 1988 बताया गया। यह उपरोक्त रिट याचिका में पारित आदेश के स्पष्ट उल्लंघन में किया गया था। उपरोक्त रिट याचिका 3 अक्टूबर, 1988 को अंतिम सुनवाई के लिए आई और निम्नलिखित आदेश के साथ निस्तारण किया गया:-

“हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता का कहना है कि ऐसे मामले जो 1988 के सीडब्ल्यूपी 72 (पियारा सिंह बनाम हरियाणा राज्य) में 26 सितंबर 1988 को दिए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के अंतर्गत आते हैं, याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। उस

निर्णय के अनुसार राहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के राज्य के अधिकार के अधीन है।

विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान के मद्देनजर, 26 सितंबर, 1988 को पियारा सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के संदर्भ में रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। याचिका की लागत, जो रुपये 500 में निर्धारित है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने कई अभ्यावेदन दायर किए, जिनमें से अंतिम था दिनांक 6 मार्च 1990। हालाँकि, याचिकाकर्ता को सेवा में वापस नहीं लिया गया

2) अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कारण बताने के लिए नोटिस जारी होने के बाद, प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में पारित आदेश की कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी। अवमानना याचिका दायर करने में देरी हुई जो अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 20 के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं थी। गुण-दोष के आधार पर यह कहा गया कि न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता से केवल एक कनिष्ठ व्यक्ति अभी भी सेवा में था अन्यथा याचिकाकर्ता सबसे कनिष्ठ था। याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश 22 जुलाई, 1988 को उसे देने की मांग की गई जब उसने आई का दौरा किया। (3) बहस के दौरान दो सवालों पर बहस हुई: (1) क्या याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं कार्यालय। हालाँकि, वह उक्त आदेश को स्वीकार किए बिना कार्यालय छोड़ गई। उसी दिन आदेश की प्रति उनके आवास पर चस्पा कर दी गई। आगे कहा गया कि पियारा सिंह का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था जिसके आधार पर याचिकाकर्ता की रिट याचिका को अनुमति दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पियारा सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता के मामले में प्रतिवादी राज्य ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की प्रार्थना के साथ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। हालाँकि, यह सुनवाई के लिए नहीं आया है।

3) बहस के दौरान दो प्रश्नों पर बहस हुई: (1) क्या उपरोक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा की यथास्थिति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और (2) क्या एस.एल.पी. के लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को सेवा में न लेने के पीछे प्रतिवादी की ओर से जानबूझकर की गई कार्रवाई है? सुप्रीम कोर्ट में पियारा सिंह के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

वीना सिक्का (श्रीमती) बनाम. श्रीमती शखुंटला जाखू (ए.एल. बहरी, जे.

4) "जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रश्न संख्या 1 पर इन कार्यवाहियों में कुछ साक्ष्य दर्ज किए गए थे। जी.एस. सक्सेना (आरडब्ल्यू 1) का बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने जुलाई को श्रीमती वीना सिक्का को पत्र-अनुलग्नक आर.2 के प्रेषण के बारे में 22. 1988, - पृष्ठांकन संख्या 352-853 के माध्यम से बताया था।। जिरह के दौरान कहा जा सकता है कि आदेश अनुलग्नक P1 वीना सिक्का की समाप्ति के संबंध में पृष्ठांकन संख्या 465 के माध्यम से 27 जुलाई, 1988 को भेजा गया था, - बहुत शुरुआत में यह हो सकता है कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया कि 21 जुलाई, 1988 के आदेश के जरिए उसकी सेवाएं समाप्त करने और 22 जुलाई, 1988 से उसे कार्यमुक्त करने की सूचना दी गई थी और यह आदेश उसके निवास पर चिपकाया गया था। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की। मामला यह है कि यह 27 जुलाई, 1988 को था जब आदेश की प्रति जिसे P1 बताया गया उसे भेजी गई थी। यह बहस के दौरान था कि याचिकाकर्ता के लिए अपने स्वयं के संक्षिप्त वकील ने पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की थी जिसे याचिकाकर्ता के आवास पर 22 जुलाई 1988 को चस्पा किया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता ने यह खुलासा नहीं किया कि उसे अपने निवास स्थान पर उपरोक्त आदेश चिपकाए जाने के बारे में कब पता चला। प्रतिवादी के इस दावे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि 22 जुलाई, 1988 को जब याचिकाकर्ता ने इस आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो इसे उसके आवास पर चिपका दिया गया था। प्रतिवादी का रुख सही प्रतीत होता है कि 25 जुलाई, 1988 को जब याचिकाकर्ता की सेवा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया गया था, तो याचिकाकर्ता को पहले ही सेवा से मुक्त कर दिया गया था और इस प्रकार इसकी आवश्यकता नहीं थी कि प्रतिवादी यथास्थिति के पूर्वोक्त आदेश के तहत याचिकाकर्ता को ड्यूटी पर फिर से शुरू करने की अनुमति दे।

5) दूसरे बिंदु के संबंध में, प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि हरियाणा राज्य से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह पियारा सिंह के मामले में निर्धारित कानून के शासन को एक अपील के रूप में इस न्यायालय में चुनौती दे। पियारा सिंह के मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पियारा सिंह के मामले में, अन्य सभी समान मामलों में, जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

पियारा सिंह के मामले पर अपने फैसले को अलग से आधारित करते हुए, प्रतिवादी से यह उम्मीद नहीं की गई थी कि वह इसे लागू करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पियारा सिंह के मामले में आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस तर्क के समर्थन में मेसर्स शेनॉय एंड कंपनी बैंगलोर और अन्य बनाम वाणिज्यिक

कर अधिकारी, सर्कल II, बैंगलोर और अन्य (1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया है। निर्णय का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि अनुपात को हाथ में लिए गए मामले पर सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। 1977 के कर्नाटक कर अधिनियम की वैधता (संक्षेप में) प्रश्न में थी। उच्च न्यायालय ने कई मामलों में इस अधिनियम को अमान्य ठहराया। एक मामले में मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया जहां अधिनियम को वैध माना गया और यह देखा गया कि अधिनियम की वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी था। यह बात महत्वहीन थी कि क्या कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की गई थी। वर्तमान मामले में किसी कानून की वैधता शामिल नहीं है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को वैध माना था। वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट को पियारा सिंह के मामले में शामिल प्रश्न (सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में) पर निर्णय लेना बाकी है। जैसा भी हो, वर्तमान मामले में भी एस.एल.पी. जैसा कि उत्तर में बताया गया है, उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रोस्टर तय करने में अपना समय लेता है। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लिया जाता, तब तक प्रतिवादी से यह उम्मीद नहीं की गई थी कि वह उपरोक्त रिट याचिका में पारित अंतिम आदेश को लागू करेगा, जो कि पियारा सिंह के मामले में निर्णय पर आधारित है, जो पहले से ही सुप्रीम में अपील का विषय है। अदालत। अवमानना कार्यवाही में यह संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की अनुमति देने पर तुरंत उत्तरदाताओं को अपील के अधिकार का सहारा लिए बिना उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने का तत्व गायब होगा। इस प्रकार, ऊपर बताई गई परिस्थितियों में इस अवमानना याचिका पर आगे बढ़ना उचित नहीं माना जाता है।

6) एक और पहलू है जिस पर विचार की जरूरत है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अंततः 3 अक्टूबर, 1988 को अनुमति दी गई, जबकि अवमानना याचिका 26 मार्च, 1990 को दायर की गई थी। न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 20 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"कोई भी अदालत अवमानना के लिए उस तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जिस दिन अवमानना का आरोप लगाया गया है, ना तो अपनी प्रेरणा से या अन्यथा, कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगी,

(7) ऊपर दर्ज कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

वीना सिक्का (श्रीमती) बनाम. श्रीमती शखुंटला जाखू (ए.एल. बहरी, जे.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा